

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं ग्रामीण युवा उद्यमिता का तुलनात्मक विश्लेषण

रणधीर सिंह¹, डॉ. सचिन कुमार²

¹शोधार्थी, ²प्रोफेसर

कृषि-विभाग

विक्रांत विश्वविद्यालय ग्वालियर म.प्र.

सारांश : ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं की उद्यमिता भारत के समावेशी आर्थिक विकास का एक महत्वपूर्ण आधार बनती जा रही है। ग्रामीण युवाओं में नवाचार, रोजगार सृजन तथा स्थानीय संसाधनों के प्रभावी उपयोग की अपार संभावनाएँ विद्यमान हैं, किन्तु वित्तीय संसाधनों की सीमित उपलब्धता उनके उद्यम स्थापना एवं विस्तार में प्रमुख बाधा के रूप में सामने आती है। इस समीक्षा शोध-पत्र का उद्देश्य ग्रामीण युवा उद्यमिता तथा वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के मध्य संबंध का तुलनात्मक विश्लेषण करना है। अध्ययन में विभिन्न सरकारी योजनाओं, बैंकिंग संस्थानों, सूक्ष्म वित्त संस्थाओं, स्वयं सहायता समूहों तथा डिजिटल वित्तीय सेवाओं की भूमिका का विश्लेषण किया गया है। साहित्य समीक्षा से यह स्पष्ट होता है कि जिन क्षेत्रों में वित्तीय पहुँच अधिक है, वहाँ ग्रामीण युवाओं की उद्यमिता अपेक्षाकृत अधिक सफल एवं टिकाऊ है। अध्ययन यह भी दर्शाता है कि वित्तीय साक्षरता, तकनीकी प्रशिक्षण तथा संस्थागत सहयोग ग्रामीण उद्यमिता को सुदृढ़ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

मुख्य संकेतक : ग्रामीण युवा, उद्यमिता, वित्तीय संसाधन, सूक्ष्म वित्त, स्टार्टअप, स्वरोजगार।

I. परिचय

भारत की लगभग 65 प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है तथा देश की युवा आबादी विश्व में सर्वाधिक है। ग्रामीण युवाओं को यदि पर्याप्त वित्तीय संसाधन, कौशल विकास तथा संस्थागत सहयोग उपलब्ध कराया जाए तो वे स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन, आय वृद्धि एवं सतत विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। वर्तमान समय में सरकार द्वारा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, स्टैंड-अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन जैसी अनेक योजनाएँ संचालित की जा रही हैं। इसके बावजूद अनेक ग्रामीण युवा वित्तीय संस्थानों तक पहुँच, ऋण स्वीकृति, जमानत की समस्या तथा वित्तीय जानकारी के अभाव के कारण उद्यम स्थापित नहीं कर पाते।

इस समीक्षा शोध-पत्र में उपलब्ध साहित्य के आधार पर वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं ग्रामीण युवा उद्यमिता का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है।



II. शोध पद्धति

यह अध्ययन द्वितीयक आँकड़ों पर आधारित समीक्षा शोध-पत्र है। इसके लिए विभिन्न शोध-पत्रों, सरकारी रिपोर्टों, RBI, NABARD, MSME मंत्रालय, नीति आयोग, विश्व बैंक, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एवं अन्य प्रकाशित साहित्य का अध्ययन किया गया है।

III. साहित्य समीक्षा

विभिन्न शोध अध्ययनों से यह स्पष्ट होता है कि वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता ग्रामीण उद्यमिता की सफलता का सबसे महत्वपूर्ण निर्धारक है। NABARD एवं RBI की रिपोर्टों के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं का विस्तार होने के बावजूद ऋण वितरण में असमानता बनी हुई है। अनेक शोधकर्ताओं ने पाया कि सूक्ष्म वित्त संस्थानों एवं स्वयं सहायता समूहों ने महिला एवं युवा उद्यमिता को प्रोत्साहित किया है। वहीं डिजिटल बैंकिंग एवं फिनटेक सेवाओं ने वित्तीय समावेशन में नई संभावनाएँ विकसित की हैं। दूसरी ओर, वित्तीय साक्षरता एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण की कमी अभी भी प्रमुख चुनौती बनी हुई है।

तालिका 1: ग्रामीण युवा उद्यमिता एवं वित्तीय संसाधनों का तुलनात्मक विश्लेषण

तुलना का आधार	पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध	सीमित वित्तीय संसाधन उपलब्ध
उद्यम स्थापना	अधिक	कम
व्यवसाय विस्तार	तीव्र	सीमित
रोजगार सृजन	अधिक	कम
नवाचार	उच्च	निम्न
जोखिम उठाने की क्षमता	अधिक	कम
आय वृद्धि	अधिक	सीमित
बाजार तक पहुँच	व्यापक	सीमित
डिजिटल तकनीक का उपयोग	अधिक	कम

तालिका 2: ग्रामीण युवाओं के लिए प्रमुख वित्तीय स्रोत

वित्तीय स्रोत	प्रमुख लाभ	प्रमुख सीमाएँ
वाणिज्यिक बैंक	कम ब्याज, अधिक ऋण	जमानत की आवश्यकता
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	ग्रामीण पहुँच	सीमित ऋण राशि
NABARD योजनाएँ	कृषि एवं ग्रामीण विकास	प्रक्रिया अपेक्षाकृत जटिल
स्वयं सहायता समूह	आसान ऋण	सीमित पूँजी
सूक्ष्म वित्त संस्थान	त्वरित ऋण	अपेक्षाकृत अधिक ब्याज
सरकारी योजनाएँ	सब्सिडी एवं सहायता	जागरूकता का अभाव



डिजिटल फिनटेक	त्वरित लेन-देन	डिजिटल साक्षरता की कमी
---------------	----------------	------------------------

IV. वित्तीय संसाधनों की भूमिका

वित्तीय संसाधन किसी भी उद्यम की स्थापना, संचालन तथा विस्तार का आधार होते हैं। ग्रामीण युवा उद्यमियों के लिए प्रारंभिक पूँजी, कार्यशील पूँजी, मशीनरी खरीद, विपणन तथा तकनीकी उन्नयन हेतु पर्याप्त वित्तीय सहायता आवश्यक होती है। जिन क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाएँ, डिजिटल भुगतान प्रणाली तथा सरकारी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन हुआ है, वहाँ ग्रामीण उद्यमिता का विकास अधिक तीव्र गति से हुआ है।

वित्तीय संसाधन किसी भी अर्थव्यवस्था, व्यवसाय अथवा उद्यम की सफलता का मूल आधार होते हैं। विशेष रूप से ग्रामीण युवा उद्यमिता के संदर्भ में वित्तीय संसाधनों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि किसी भी नए उद्यम की स्थापना, संचालन, विस्तार तथा स्थायित्व के लिए पर्याप्त पूँजी की आवश्यकता होती है। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले अधिकांश युवा सीमित आर्थिक साधनों से जुड़े होते हैं, जिसके कारण वे अपने व्यावसायिक विचारों को व्यवहार में परिवर्तित नहीं कर पाते। यदि उन्हें समय पर उचित मात्रा में वित्तीय सहायता, सरल ऋण सुविधा तथा अन्य आर्थिक संसाधन उपलब्ध हो जाएँ, तो वे स्वरोजगार के माध्यम से न केवल अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बना सकते हैं, बल्कि स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर भी उत्पन्न कर सकते हैं। वित्तीय संसाधनों का महत्व केवल प्रारंभिक निवेश तक सीमित नहीं है।

बल्कि यह उत्पादन, विपणन, तकनीकी उन्नयन, मानव संसाधन विकास, नवाचार तथा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता को बढ़ाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ग्रामीण युवाओं के लिए बैंक ऋण, सूक्ष्म वित्त, स्वयं सहायता समूह, सहकारी समितियाँ, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, नाबार्ड, मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, स्टार्टअप इंडिया तथा स्टैंड-अप इंडिया जैसी योजनाएँ वित्तीय संसाधनों के प्रमुख स्रोत हैं। इन योजनाओं के माध्यम से सरकार ग्रामीण युवाओं को कम ब्याज दर पर ऋण, अनुदान, सब्सिडी तथा प्रशिक्षण उपलब्ध कराकर उद्यमिता को बढ़ावा देने का प्रयास कर रही है। वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता से युवा आधुनिक मशीनरी, उन्नत तकनीक, गुणवत्तापूर्ण कच्चा माल तथा डिजिटल उपकरणों का उपयोग कर अपने व्यवसाय की उत्पादकता एवं गुणवत्ता में वृद्धि कर सकते हैं।

इसके अतिरिक्त, पर्याप्त पूँजी होने पर वे बाजार अनुसंधान, ब्रांडिंग, विज्ञापन तथा ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म का उपयोग करके अपने उत्पादों एवं सेवाओं का व्यापक स्तर पर विपणन कर सकते हैं। वर्तमान डिजिटल युग में डिजिटल भुगतान प्रणाली, ऑनलाइन बैंकिंग तथा फिनटेक सेवाओं ने ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन को नई दिशा प्रदान की है। जन-धन योजना, आधार आधारित भुगतान प्रणाली, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस तथा मोबाइल बैंकिंग जैसी सुविधाओं ने ग्रामीण युवाओं के लिए वित्तीय लेन-देन को सरल, सुरक्षित एवं पारदर्शी बनाया है। इससे उद्यमियों को समय की बचत होने के साथ-साथ औपचारिक वित्तीय प्रणाली से जुड़ने का अवसर भी प्राप्त हुआ है। वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता जोखिम वहन करने की क्षमता को भी बढ़ाती है।

कोई भी नया व्यवसाय प्रारंभ करते समय अनेक प्रकार की अनिश्चितताएँ एवं जोखिम होते हैं, जैसे बाजार में मांग का उतार-चढ़ाव, प्रतिस्पर्धा, प्राकृतिक आपदाएँ तथा उत्पादन लागत में वृद्धि। पर्याप्त वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता उद्यमियों को इन जोखिमों का प्रभावी ढंग से सामना करने में सक्षम बनाती है। इसके विपरीत, वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण अनेक ग्रामीण युवा अपने व्यवसाय को प्रारंभिक अवस्था में ही बंद करने के लिए विवश हो जाते हैं। वित्तीय संसाधन नवाचार एवं उद्यमिता के विकास में भी



अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब युवाओं को पर्याप्त पूँजी उपलब्ध होती है, तब वे नए उत्पादों, नई तकनीकों तथा नवीन व्यावसायिक मॉडलों पर कार्य करने के लिए प्रेरित होते हैं।

इससे स्थानीय संसाधनों का बेहतर उपयोग होता है तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था में विविधता एवं प्रतिस्पर्धात्मकता का विकास होता है। कृषि आधारित उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण, डेयरी, मत्स्य पालन, हस्तशिल्प, कुटीर उद्योग, डिजिटल सेवाएँ तथा ग्रामीण पर्यटन जैसे क्षेत्रों में वित्तीय सहायता प्राप्त युवा उद्यमी सफलतापूर्वक नए रोजगार अवसर उत्पन्न कर रहे हैं। वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन का भी महत्वपूर्ण माध्यम है। सफल ग्रामीण उद्यमी अपने क्षेत्र में अन्य युवाओं को भी प्रेरित करते हैं, जिससे उद्यमिता की संस्कृति विकसित होती है। इससे पलायन की समस्या कम होती है, स्थानीय आय में वृद्धि होती है तथा ग्रामीण क्षेत्रों का समग्र विकास संभव हो पाता है।

महिलाओं एवं वंचित वर्गों के लिए भी वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता विशेष महत्व रखती है। स्वयं सहायता समूहों एवं सूक्ष्म वित्त संस्थानों द्वारा प्रदान किए गए ऋण ने ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अनेक अध्ययन यह दर्शाते हैं कि महिला उद्यमियों द्वारा स्थापित छोटे व्यवसाय परिवार की आय, बच्चों की शिक्षा तथा सामाजिक विकास में सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। यद्यपि सरकार एवं विभिन्न वित्तीय संस्थानों द्वारा अनेक योजनाएँ संचालित की जा रही हैं, फिर भी ग्रामीण युवाओं को वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता में अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।

इनमें बैंक ऋण प्राप्त करने की जटिल प्रक्रिया, जमानत की अनिवार्यता, सीमित वित्तीय साक्षरता, परियोजना निर्माण का अभाव, दस्तावेजी औपचारिकताओं की कठिनाई तथा सरकारी योजनाओं की अपर्याप्त जानकारी प्रमुख हैं। अनेक ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक शाखाओं एवं वित्तीय परामर्श सेवाओं की सीमित उपलब्धता भी एक महत्वपूर्ण समस्या है। इसके अतिरिक्त, कई युवा जोखिम लेने से बचते हैं क्योंकि उन्हें व्यवसाय प्रबंधन एवं वित्तीय नियोजन का पर्याप्त प्रशिक्षण प्राप्त नहीं होता। इसलिए आवश्यक है कि वित्तीय सहायता के साथ-साथ कौशल विकास, उद्यमिता प्रशिक्षण, वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम तथा व्यवसाय परामर्श सेवाओं को भी सुदृढ़ बनाया जाए। वित्तीय संस्थानों, शैक्षणिक संस्थानों, उद्योग संगठनों तथा सरकारी एजेंसियों के बीच समन्वय स्थापित कर ग्रामीण युवाओं को समग्र सहयोग प्रदान किया जाना चाहिए।

डिजिटल वित्तीय सेवाओं के विस्तार, सरल ऋण प्रक्रियाओं, बिना जमानत वाले ऋण, कम ब्याज दर, क्रेडिट गारंटी योजनाओं तथा नियमित वित्तीय परामर्श के माध्यम से ग्रामीण उद्यमिता को अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। अंततः यह कहा जा सकता है कि वित्तीय संसाधन ग्रामीण युवा उद्यमिता की आधारशिला हैं। इनके बिना किसी भी उद्यम की कल्पना करना कठिन है। पर्याप्त एवं सुलभ वित्तीय संसाधन न केवल नए व्यवसायों की स्थापना को संभव बनाते हैं, बल्कि उनके दीर्घकालिक विकास, नवाचार, प्रतिस्पर्धात्मकता तथा रोजगार सृजन को भी सुनिश्चित करते हैं। यदि वित्तीय समावेशन, वित्तीय साक्षरता तथा संस्थागत सहयोग को और अधिक सुदृढ़ किया जाए, तो ग्रामीण युवा भारत की आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था, समावेशी विकास तथा सतत आर्थिक प्रगति के प्रमुख वाहक सिद्ध हो सकते हैं।

v. ग्रामीण युवा उद्यमिता की प्रमुख चुनौतियाँ

1. वित्तीय संसाधनों की कमी।
2. बैंक ऋण प्राप्त करने में कठिनाई।



3. जमानत एवं दस्तावेजों की समस्या।
4. वित्तीय साक्षरता का अभाव।
5. बाजार संबंधी जानकारी की कमी।
6. तकनीकी एवं प्रबंधकीय प्रशिक्षण का अभाव।
7. डिजिटल बैंकिंग का सीमित उपयोग।
8. सरकारी योजनाओं की जानकारी का अभाव।

VI. सरकारी योजनाओं की भूमिका

भारत सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाएँ ग्रामीण युवाओं को उद्यमिता के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

योजना	उद्देश्य
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना	सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों हेतु ऋण
पीएमईजीपी	रोजगार सृजन
स्टार्टअप इंडिया	नवाचार आधारित उद्यम
स्टैंड-अप इंडिया	अनुसूचित जाति, जनजाति एवं महिला उद्यमी
राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन	स्वरोजगार एवं SHG विकास
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना	कौशल प्रशिक्षण

VII. चर्चा

समीक्षा से स्पष्ट होता है कि वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं ग्रामीण युवा उद्यमिता के मध्य प्रत्यक्ष एवं सकारात्मक संबंध है। जिन राज्यों में बैंकिंग सुविधाएँ, स्वयं सहायता समूह, सूक्ष्म वित्त संस्थान तथा सरकारी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन हुआ है, वहाँ उद्यम स्थापना की दर अधिक पाई गई। इसके विपरीत वित्तीय पहुँच की कमी वाले क्षेत्रों में युवा उद्यमिता का विकास अपेक्षाकृत धीमा है। डिजिटल वित्तीय सेवाओं ने वित्तीय समावेशन को बढ़ावा दिया है, किन्तु डिजिटल साक्षरता की कमी अभी भी एक बड़ी चुनौती है।

VIII. निष्कर्ष

ग्रामीण युवा उद्यमिता भारत के आर्थिक एवं सामाजिक विकास की आधारशिला बन सकती है, यदि उसे पर्याप्त वित्तीय संसाधन, कौशल विकास एवं संस्थागत सहयोग प्राप्त हो। समीक्षा अध्ययन से स्पष्ट है कि वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता उद्यम स्थापना, व्यवसाय विस्तार, नवाचार तथा रोजगार सृजन को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। सरकारी योजनाओं, बैंकिंग संस्थानों, स्वयं सहायता समूहों तथा डिजिटल वित्तीय सेवाओं के समन्वित प्रयासों से ग्रामीण युवाओं को आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है। भविष्य में



वित्तीय समावेशन, डिजिटल साक्षरता एवं उद्यमिता प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान देकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को अधिक सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है।

संदर्भ

1. केशरी, पी., और तिवारी, ए. के. (2026). ग्रामीण क्षेत्र में वित्तीय समावेशन—एक समीक्षा और अनुसंधान एजेंडा। फ्यूचर बिजनेस जर्नल, 12, लेख 49।
2. गर्ग, एस., गुप्ता, एस., और मल्लिक, एस. (2025). लिंग के आधार पर वित्तीय पहुंच और उद्यमिता: ग्रामीण भारत से साक्ष्य। लघु व्यवसाय अर्थशास्त्र, 64(2), 729–754.
3. गर्ग, एस., गुप्ता, एस., और मल्लिक, एस. (2026)। क्या सामाजिक पहचान ग्रामीण उद्यमिता को बाधित करती है? वित्तीय समावेशन की भूमिका पर साक्ष्य। जर्नल ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, 179, 103669।
4. मोर, एम.एम., पंडित, वी., उद्रे, के., कुलकर्णी, वी., सोमन्नावर, जी., और रंडीवे, एस. (2026)। भारत में ग्रामीण युवाओं के बीच डिजिटल भुगतान को अपनाना और वित्तीय समावेशन। इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी में बहुविषयक अनुसंधान जर्नल, 13(2), 321–328।
5. सरिता, और अरोरा, एस. (2026)। बैंकिंग सुविधाओं से वंचितों को बैंकिंग सुविधा प्रदान करना: ग्रामीण व्यापारियों और महिला उद्यमियों के लिए वित्तीय समावेशन। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ फाइनेंस एंड कॉमर्स, 8(2), 25–30।
6. सीनान, आर. ए., मूडीथया, एम. एस., और हैंडी, एफ. (2012). वित्तीय समावेशन: ग्रामीण दक्षिण भारत से सबक। जर्नल ऑफ सोशल पॉलिसी, 41(1), 183–205.

